Violation of UGC rules by State Universities

3114. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government are aware that many State Universities in the country are imparting one year undergraduate degree course by violating UGC rules;

(b) if so, whether the UGC propose to take any legal action against such universities; and

(c) the details of such universities and the action Government propose to take to ensure implementation of UGC rules?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF EDUCATION IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI MUHI RAM SAIKIA): (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

नदियों में प्रदूषण के नियंत्रण हेतु विदेशी सहायता

3115. **श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्ल:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश की प्रमुख नदियों को प्रदूषण मुक्त करने हेतु वित्तीय सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो उन योजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनके अन्तर्गत देश-वार सहायता मिलने की संभावना है;

(ग) किन-किन नदियों को प्रदूषण मुक्त करने हेतु विश्व बैंक से भी सहायता मांगी है; और

(घ) यह सहायता कब तक प्राप्त हो जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद): (क) जी, हां।

(ख) उन योजनाओं वाला विवरण संलग्न है जिनके अन्तर्गत सहायता प्राप्त होने की संभावना है **(नीचे देखिए)**

(ग) और (घ) पंजाब के सतलुज नदी के प्रदूषण निवारण के लिए विश्व बैंक से सहायता मांगी गई थी। विश्व बैंक ने धन प्रदान करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है।

विवरण

नदी प्रदूषण रोकने की उन स्कीमों का विवरण जिनके अन्तर्गत सहायता प्राप्त होनी है।

क्र०सं०	स्कीम का नाम	जिस देश से सहायता मिलनी है	सहायता जब तक अपेक्षित
1.	गंगा कार्य योजना चरण-II (कानपुर)	नीदरलैण्ड	1996-97
2.	इंडस्ट्रियल काउसलिंग टैनरीज-II (कानपुर)	नीदरलैण्ड	नीदरलैण्ड सरकार के अंतर्गत विचाराधीन
3.	लखनऊ में गोमती कार्य योजना (सहायता का दूसरा चरण)	यूनाइटेड किंगडम का ओवरसीज डेवलमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ओ०डी०ए० (यू०के०)	सही समय का पता मार्च 1997 के बाद पता चलेगा
4.	मद्रास के शहर के तटीय क्षेत्र में प्रदूषण निवारण	यूरोपीय इकोनामिक कम्यूनिटी	यूरोपीय इकोनामिक कम्यूनिटी के अंतर्गत विचाराधीन